छिंदवाड़ा | बुधवार | 24 जून 2026 | वर्ष 26 | अंक 76 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 देशभर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार

4 रिफॉर्म के अंतर्गत बढ़ रही न्यायिक सुगमता

9 पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की बढ़ी उम्मीद

8 मेसी बने विश्व कप इतिहास के टॉप स्कोरर

बीजेपी की कार्यसमिति घोषित

सदस्यों की संख्या 106 तक कर दिया सीमित

41 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी खंडेलवाल टीम में शामिल

33 फीसदी महिलाओं को भी भाजपा ने दिया मौका

15 जुलाई को ओरछा में होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक

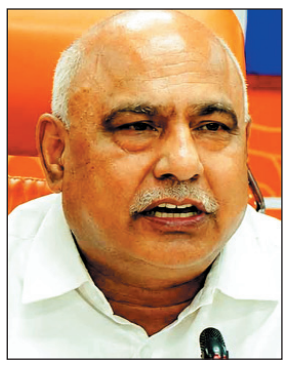

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 जून. लंबे इंतजार के बाद भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति आखिरकार घोषित कर दी गई है. भाजपा के अलग- अलग गुटों के दबाव को दरकिनार करते हुए संगठन ने पार्टी के संविधान को तवज्जो दी है और सदस्यों की संख्या को महज 106 तक सीमित कर दिया है.

106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति में भाजपा ने नारी शक्ति को पूरा सम्मान देते हुए 33 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया है. इसके साथ ही टीम खंडलेवाल में 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं. इस तरह दोनों ही तरह के सदस्यों को मिलाकर कुल 147 सदस्य शामिल किए गए हैं.

पिछली भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में 200 सदस्य शामिल किए गए थे, वहीं स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या 22 थी, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 235 सदस्य शामिल थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जो प्रदेश कार्यसमिति घोषित की है, उसमें सभी संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष और प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक को प्रदेश कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य का रूतबा दिया गया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कार्यसमिति में सभी वर्गों, समाजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रयास किया गया है. कार्यसमिति में अजा, जजा, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है.

कार्यसमिति का गठन भाजपा के सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के आधार पर किया गया है.15 जुलाई को ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

(शेष पेज 6 पर)

स्थाई आमंत्रित सदस्य

सत्यनारायण जटिया, सुमित्रा महाजन, कृष्णमुरारी मोघे, कप्तान सिंह सोलंकी, माखन सिंह, सुरेश पचौरी, सीतासरन शर्मा, गिरीश गौतम, गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, अनुसुईया उइके, दीपक सक्सेना, कैलाश सोनी, विवेक नारायण शेजवलकर, रघुनंदन शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, कुसुम मेहदेले, अजय विश्नोई, हिम्मत कोठारी, अनूप मिश्रा, गौरीशंकर बिसेन, गौरीशंकर शेजवार, ढालसिंह बिसेन, कैलाश चावला, भागीरथ प्रसाद, जितेन्द्र जामदार, बाबू सिंह रघुवंशी, वेदप्रकाश शर्मा, तपन भौमिक, माया सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, नानाभाऊ माहोड़, सुधा जैन, श्रीमती कृष्णकांता तोमर, अलका जैन, जगदीश अग्रवाल, विसाहूलाल सिंह, नागेन्द्र सिंह नागौद, मधु वर्मा और ज्ञान सिंह .

अलीगंज अग्निकांड पर सीएम योगी का एक्शन

04 चार आरोपी गिरफ्तार

04 अफसर किए सस्पेंड

लखनऊ, 23 जून. लखनऊ में अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं. अलीगढ़ में कार्यक्रम रद्द कर सीधे लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले घटनास्थल का जायजा लिया, फिर केजीएमयू में घायलों से मिले. इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक कर चार आरोपियों की गिरफ्तारी और चार अफसरों को निलंबित करने के निर्देश दिए. हादसे के वक्त मुख्यमंत्री अलीगढ़ में लोगों को संबोधित कर रहे थे. मंच से ही घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने सभी कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ रवाना होने की घोषणा की. इससे पहले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अफसरों को मौके पर भेजकर राहत-बचाव के निर्देश दिए थे. लखनऊ पहुंचते ही योगी सीधे अलीगंज घटनास्थल पहुंचे और राहत-बचाव कार्य देखा. इसके बाद केजीएमयू ट्रामा सेंटर जाकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद का ऐलान किया.

B.Arch
Approved by CoA
AND
• Bachelor of Interior Design
• Master of Interior Design
• M. Plan#
(Urban & Regional Planning)
#Approved by ITPI | Lateral Entry progs also offered

Scholarships* | 100% | 50% | 25%
UG Programmes
12th (agg.) | 93% | 88% | 70%
PG Programmes (Non-MBA)
12th (agg.) | 93% | 88% | -
Graduation (agg.) | 80% | 75% | -
*Offered in 56+ progs across various disciplines

To apply visit:
amity.edu/gwalior
by: 27th June 2026
7303-872-872

AMITY UNIVERSITY GWALIOR
Futuristic Design Pathways
• Hi-end design & materials lab and software platforms like GIS Tools, GeoMedia & GeoMedia Professional, BIM-Autodesk Revit, Civil 3D, AutoCAD, Map 3D, SketchUp Pro, ArcGIS, V-Ray, Lumion...
• Hands-on learning with 3D printing, model making & digital fabrication
• On-campus Centre for Excellence for Gwalior as a Smart City
• Top recruiters include Dutta Kannan Architects, The Design Studio, TOD Innovations, Living Aura Interior, PAN Architecture, Cube Collective, Interior World...
• Ranked #1 in Madhya Pradesh (Pvt) '26 by QS Southern Asia
• Ranked amongst top 2 in MP (Pvt) '26 - India's Best Multidisciplinary Universities by The Week-Hansa
• Optional Study Abroad Program in New York, Singapore, London, France, Dubai or Australia to study international design ethos & sustainability standards amongst other academic contours
Maharajpura, Gwalior (Opp. Airport) | E: admissions@gwa.amity.edu

200 करोड़ की वित्तीय हेराफेरी का आरोप

- एलएनसीटी ग्रुप के परिसरों में छापा
- ईडी और ईओडब्लू की टीम कर रही कार्रवाई

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 23 जून. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एलएनसीटी ग्रुप के रायसेन, कोलार सहित परिसरों में छापेमारी की. ईडी के साथ ही इस मामले में ईओडब्लू की टीम भी कार्रवाई में जुटी है. आरोप है कि 200 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय हेराफेरी हुई है.

जानकारी के अनुसार ईओडब्लू में मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने कार्रवाई की है. ग्रुप के शैक्षणिक संस्थानों और उससे जुड़े ठिकानों पर इसके चलते छापा मारा गया. भोपाल के अलावा ग्रुप के अन्य परिसर में भी ईडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल जारी है. मामले की आधिकारिक तौर पर जांच एजेंसियों ने विवरण को साझा अभी तक नहीं किया है.

सूत्रों के मुताबिक एलएनसीटी के वित्तीय दस्तावेजों, बैंक के रिकॉर्डस, अकाउंट स्टेटमेंट सहित डिजिटल साक्ष्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं. मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्लू) ने ग्रुप के प्रमोटर चौकसे परिवार के खिलाफ 200 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज किया था. ईडी ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं की एलएनसीटी ग्रुप की अब जांच शुरू कर दी है. (शेष पेज 6 पर)

एक नजर में

मुर्मु ने मंत्री कुरियन का इस्तीफा स्वीकार किया

नई दिल्ली 23 जून. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के अंतर्गत श्री कुरियन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. श्री कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे. उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. मोदी सरकार ने उन्हें हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था. वह राज्यसभा में मध्य प्रदेश से चुनकर आए थे और 21 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था.

65 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार

नई दिल्ली, 23 जून. राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को 'नागरिक अलंकरण समारोह-द्वितीय' में 'पद्म पुरस्कार- 2026' प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया।

इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत) को पद्म भूषण से सम्मानित किया. उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने सम्मान प्राप्त किया। वहीं, टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति मुर्मु ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस दौरान पी. नारायणन और जस्टिस (रिटायर्ड) केटी थॉमस को साहित्य और शिक्षा तथा जन-कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पाने वाले अन्य लोगों में एसकेएम मैलानंदन, ममूटी, वेल्लापल्ली नटेसन और दत्तात्रेयुडु नोरी शामिल हैं। अवॉर्ड पाने वालों की लिस्ट में दो अमेरिकी, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक भी शामिल हैं. राष्ट्रपति मुर्मु ने अलंकरण समारोह में 65 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे. दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण, और 56 पद्म श्री शामिल हैं।

संघ की दिवाली बैठक होगी महत्वपूर्ण

10 दिनों तक इंदौर में ही कैंप करेंगे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

मिलिंद मुजुमदार

इंदौर, 23 जून. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक नवंबर में इंदौर में होगी। इस बैठक को संघ की दिवाली बैठक कहा जाता है. दिवाली बैठक में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत करीब 10 दिनों तक इंदौर में कैंप करेंगे। उनके अलावा संघ के लगभग 150 शीर्ष पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे.

इसी वर्ष अक्टूबर के विजयदशमी के दिन संघ के शताब्दी समारोहों का समापन होगा. इंदौर की बैठक में शताब्दी समारोह कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ संगठन के विस्तार और अनुषांगिक संगठनों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी. यह बैठक तीन दिन चलेगी, लेकिन इसके लिए डॉ. मोहन भागवत करीब 10 दिनों तक इंदौर में रहेंगे।

सरकार के कामकाज की होगी अनौपचारिक समीक्षा

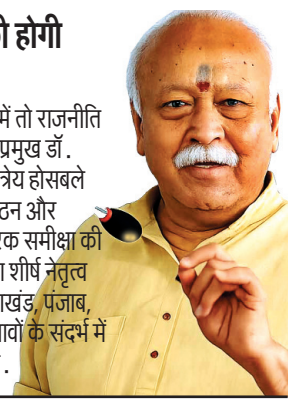

सूत्रों के अनुसार, औपचारिक बैठक में तो राजनीति पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा के संगठन और सरकार के कामकाज की अनौपचारिक समीक्षा की जा सकती है. इसके अलावा, संघ का शीर्ष नेतृत्व 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भाजपा नेताओं से चर्चा कर सकता है.

गुस्ताखी माफ

नए अवसर किसानों की आय बढ़ाने वाला वैश्विक व्यापार समझौता

ब्रिटेन बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत एंट्री

नई दिल्ली, 23 जून. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) वास्तव में लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया समझौता है, जिससे भारतीय किसानों, कारोबारियों, कारीगरों और देश भर के आम लोगों को लाभ मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ब्रिटेन के प्रीमियम बाजार तक पहुंच मिलने से महिला उद्यमियों, युवाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खुलेंगे. साथ ही यह समझौता भारत के मूल हितों से समझौता किए बिना वंचित वर्गों को भी सशक्त बनाएगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद करेगा.

मंत्री पीयूष गोयल ने अपने लेख में बताया कि 15 जुलाई से लागू होने वाला यह परिवर्तनकारी और दोनों देशों के लिए लाभकारी समझौता भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा, खासकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में. इसके तहत लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, जो लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे.